Opening Remarks of the Comptroller and Auditor General of India at the 6th SCO SAI Leaders meeting on 6th February, 2023 at Lucknow.

लखनऊ में 6 फरवरी, 2023 को छठी एससीओ साई नेताओं की बैठक में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उद्घाटन टिप्पणी।

उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल

Ms. Natalya Godunova, कजाकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम ऑडिट चैंबर के अध्यक्ष,

Mr. ZHANG Ke, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय के उप महालेखा परीक्षक,

Mr. Almazbek Akmatov Sharshembievich, किर्गिज़ गणराज्य के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष,

Mr. Syed Sajjad Hyder, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अतिरिक्त महालेखापरीक्षक,

Mr. Timur Makhmutov, रूसी संघ के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग विभाग के निदेशक,

Mr. Chillazoda Karakhon, ताजिकिस्तान गणराज्य के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष

Mr. Turabov Bakhodir Tukhtamishovich, उजबेकिस्तान गणराज्य के चैंबर ऑफ अकाउंट्स के अध्यक्ष और

Mr. Nuran Niyazaliev, उप महासचिव, एससीओ सचिवालय सम्मानित सहयोगी, देवियों और सज्जनों

नमस्ते, सुप्रभात और छठी एससीओ साई प्रमुख की बैठक में हार्दिक स्वागत।

1. माननीय राज्यपाल महोदय, छठे एससीओ साई प्रमुख की बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में आपका स्वागत करना वास्तव में हम सभी के लिए एक सम्मान और सौभाग्य की बात है, और हम आपके संबोधन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं।

महामहिम,

2. प्रारंभ में, मैं मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल म्होदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल का संक्षिप्त परिचय कराता हूं। श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने एक शिक्षक और एक राजनीतिज्ञ के रूप में लोगों की सेवा की है और 1994 से 1998 तक राज्यसभा

के सदस्य के रूप में, गुजरात में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है और 2014 से 2016 तक गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू कीं जैसे कि गरीबों को चिकित्सा उपचार के लिए मां वात्सल्य योजना, गरीब छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए युवा स्वावलंबन योजना, महिलाओं के लिए मुफ्त कैंसर जांच और उपचार; और सिंचाई, परिवहन, नगर-नियोजन आदि के क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं को लागू किया। उन्हें शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अन्य सम्मानों के अलावा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार और दो छात्राओं को डूबने से बचाने के लिए गुजरात सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार सहित कई सम्मान और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

माननीय राज्यपाल,

3. जैसा कि आप जानते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) एक आठ सदस्यीय बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को

शंघाई, चीन में; जब चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई थी, तब शंघाई सहयोग संगठन की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। जून 2002 में, एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों ने एससीओ चार्टर पर हस्ताक्षर किए, जिसने संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों, संरचनाओं और संचालन के स्वरूपों को परिभाषित किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में स्थापित किया। जुलाई 2005 के अस्ताना शिखर सम्मेलन में, भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में, भारत आधिकारिक तौर पर एससीओ में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ।

Excellencies

4.भारत एससीओ क्षेत्र के साथ सम्मानित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है। विविध लोगों और परिदृश्यों की इस विशाल भूमि ने मानव जाति की प्रगति में भरसक योगदान दिया है। क्षेत्रों को पार करने वाले मार्गों का नेटवर्क न केवल माल और व्यापार के आदान-प्रदान के लिए महत्वपूर्ण था, बल्कि विचारों के आदान-प्रदान करने और विज्ञान और कला जैसे बौद्धिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता था।

Excellencies

5. आप इस बात से सहमत होंगे कि उच्चतम लेखा परीक्षा संस्थान (साई) सरकार में सुशासन और जवाबदेही को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकारी वित्त और संचालन की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार स्वतंत्र निकायों के रूप में यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का कुशलतापूर्वक, प्रभावी ढंग से और कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हुये उपयोग किया जा रहा है। साई सुधार के क्षेत्रों की पहचान करके, अक्षमताओं को उजागर करके, और धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के संभावित क्षेत्रों की पहचान करके राष्ट्रीय सरकारों को बेहतर अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं।

6. अपनी साझा जिम्मेदारियों को आगे बढ़ाने के लिए, और पांच सफल बैठकों के बाद, हम 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' और 'साइबर सुरक्षा' विषयों के साथ 'लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने' के एजेंडे पर विचार-विमर्श करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए एकत्र हुए हैं।

Excellencies,

7. आप यह समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) मशीनों में मानव बुद्धि के अनुकरण को संदर्भित करता है जो मनुष्यों की तरह सोचने और सीखने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। एआई एक व्यापक

क्षेत्र है जिसमें मशीन लर्निंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, कंप्यूटर विजन, और विशेषज्ञ प्रणालियों सहित कई अलग-अलग तकनीकें और दृष्टिकोण शामिल हैं। इन तकनीकों का उपयोग विकसित प्रणालियों का निर्माण करने के लिए किया जाता है जो सरल से जटिल कार्यों की एक विस्तृत श्रृंखला पूरी कर सकते हैं, , जैसे भाषा पहचानना, वस्तुओं की पहचान करना, भविष्यवाणियां करना, और गेम खेलना।

Excellencies,

8. सामान्य रूप से प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी में दुनिया की सबसे कठिन चुनौतियों - जलवायु, गरीबी, भोजन, ईंधन, स्वास्थ्य और सुरक्षा का समाधान करने की क्षमता है। दुनिया भर की सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में एआई का उपयोग कर रही हैं, जिसमें स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, अपराध और सुरक्षा, कृषि में नवाचार, सरकारी सेवाओं का प्रावधान और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रयास शामिल हैं। एआई,; साई सहित सरकारी एजेंसियों को कार्यों को स्वचालित करने, डेटा का विश्लेषण करने, दक्षता में सुधार करने, न केवल लागत को कम करने, और अधिक प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में सहायता कर सकता है, बल्कि भविष्यसूचक

विश्लेषिकी, नियमित कार्यों के स्वचालन, स्मार्ट शहरों, सार्वजनिक सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाने और रोकथाम, नागरिक सेवाओं, और स्वास्थ्य सेवा में भी सहायता कर सकता है।

Excellencies,

9. भारत तेजी से एक प्रौद्योगिकी पावरहाउस के रूप में बढ़ रहा है**,** क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालक हैं**,** जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में **13%** से अधिक का योगदान देते हैं। भारत की प्रौद्योगिकी**;** उद्योग विकास में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया**,** वित्त वर्ष **2022** में राजस्व में **$ 227** बिलियन तक पहुंच गया**,** जो पिछले वर्ष **$ 200** बिलियन से अधिक है। देश का आईटी खर्च 2022-23 में 7% बढ़कर 101.8 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। इसके साथ-साथ, काफी बड़ी संख्या में उपयोगकर्ताओं ने मैलवेयर या अन्य हमलों का अनुभव किया है। यह विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि खरबों ऑनलाइन लेनदेन किए जाते हैं जबकि अरबों डॉलर हर साल ऑनलाइन निवेश किए जाते हैं। इन चुनौतियों का सामना न केवल नीति निर्माताओं**,** कार्यक्रम और परियोजना को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा किया जाना है**,** बल्कि साई को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि वे जोखिम शमन उपायों की नीति का

मूल्यांकन करते हैं। इससे एआई और साइबर सुरक्षा चुनौतियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर अनुभवों को साझा करना अनिवार्य हो जाता है।

10. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि साई इंडिया ऑडिट की गई संस्थाओं से एकत्र किए गए आंकड़ों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों का उपयोग कर रहा है। एआई तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से पहचाने गए जोखिम क्षेत्रों या रुचि के क्षेत्रों का उपयोग लेखापरीक्षा उद्देश्यों की पहचान करने और लेखापरीक्षा योजना चरण के दौरान ऑडिट डिजाइन मैट्रिक्स विकसित करने के लिए किया जाता है। यह लेखा परीक्षा प्रक्रिया के लिए अधिक लक्षित और कुशल दृष्टिकोण का अवसर देता है।

11. इसके अतिरिक्त, साई इंडिया इन-पर्सन ऑडिट के लिए नमूना इकाइयों के विशिष्ट और केंद्रित सेट की पहचान करने के लिए एआई तकनीकों का भी उपयोग कर रहा है। यह डेटा से पहचाने गए संभावित विचलन के समर्थन में पुष्टि करने वाले साक्ष्य के संग्रह की अनुमति देता है। संगठन ऑडिट की गई संस्थाओं से समय-समय पर डेटा प्राप्त करने और मॉडल को बेहतर बनाने के लिए वास्तविक जांच से प्रतिक्रिया

शामिल करने की दिशा में भी काम कर रहा है। यह नए डेटा स्रोतों को शामिल करने और एआई मॉडल के आगे के प्रशिक्षण और शोधन की अनुमति देता है।

12. परिणामस्वरूप, साई इंडिया एआई के उपयोग को एक विशिष्ट लेखा परीक्षा कार्य के लिए एकल प्रक्रिया के रूप में नहीं देखता है, बल्कि ऑडिट योजना और निष्पादन दोनों चरणों के दौरान त्वरित और अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए एक विकसित एआई मॉडल के निर्माण के रूप में देखता है। यह ऑडिट प्रक्रिया के लिए अधिक कुशल और प्रभावी दृष्टिकोण प्रदान करता है और ऑडिट की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

Excellencies,

13. किसी भी नई तकनीक के आने से उसके पक्ष और विपक्ष प्रतिध्वनित करने वाले विवाद छिड़ जाते हैं। सरकार द्वारा एआई का उपयोग नैतिक और शासन संबंधी समस्याओं को भी उठाता है, जिसमें डेटा गोपनीयता और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। निष्पक्ष एआई की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

Excellencies,

14. सरकारी परिचालनों के डिजिटलीकरण और उन्नत/उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने से इसकी अपनी चुनौतियां और जिम्मेदारियां भी आई हैं और एआई संचालित उन्नत मैलवेयर से बचाव हुआ है। इस प्रकार, पारंपरिक साइबर-सुरक्षा खतरे के खिलाफ विभिन्न मौजूदा प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और तरीको के उपयोग को शामिल करना सिस्टम, नेटवर्क आदि की सुरक्षा का तरीका है, एआई का उपयोग साइबर-सुरक्षा में भी आक्रामक और रक्षात्मक भूमिकाओं के लिए किया जा रहा है क्योंकि एआई संचालित उन्नत पॉलीमॉर्फिक मैलवेयर / ट्रोजन से खतरे हैं जो अपने व्यवहार को बदलने और सुरक्षा कवच को बायपास करने की क्षमता रखते हैं।

15. साइबर अपराध एक बड़ा आर्थिक खतरा बन गया है, जिसपर वैश्विक अर्थव्यवस्था का सालाना $ 6 ट्रिलियन से अधिक व्यय होने का अनुमान है, जिसके 2025 तक लगभग $ 10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। साइबर अपराधियों का अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने का इतिहास है, और एआई कोई अपवाद नहीं है। ऐसी खबरें हैं कि एआई संचालित मैलवेयर को वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी), सुरक्षा सॉफ्टवेयर और स्पैम फिल्टर जैसे दो कारक प्राधिकरणों से बचने के लिए विकसित किया जा रहा है। पासवर्ड का अनुमान लगाने और सोशल मीडिया प्रोफाइल का

विश्लेषण करने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग किया जा रहा है। साइबर अपराधी अब अपने टारगेट को धोखा देने के लिए नकली फोटो, ऑडियो और वीडियो बनाने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं। ये दुर्भावनापूर्ण एआई एप्लिकेशन अपराधियों के लिए जानकारी इकट्ठा करना, लोगों को धोखा देना और संवेदनशील जानकारी चुराना आसान बनाते हैं, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों की आवश्यकता बढ़ जाती है। इस प्रकार, मुख्य चुनौतियों में से एक साइबर खतरों का निरंतर बढ़ना है। जिससे सरकारों के लिए नवीनतम जोखिमों और असुरक्षा से बचना मुश्किल हो जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकारों के पास सामान्यतः साइबर सुरक्षा के लिए सीमित संसाधन होते हैं, जो उनकी प्रणाली और नेटवर्क की रक्षा करने की उनकी क्षमता में बाधा बन सकते हैं। एक और चुनौती जिसका सरकारें सामना करती हैं वह लेगसी सिस्टम्स की उपस्थिति है। कई सरकारी प्रणालियां और नेटवर्क पुरानी तकनीक पर आधारित हैं, जो आधुनिक साइबर खतरों का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। इन प्रणालियों को अपग्रेड करना महंगा और समय लेने वाला हो सकता है, जिससे सरकारों के लिए अपने सिस्टम को सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाता है।

सरकारों को साइबर सुरक्षा में सुधार के लिए निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता के साथ संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा की आवश्यकता को संतुलित करने की भी आवश्यकता है।

16. अंत में, साइबर सुरक्षा खतरे अक्सर राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान नहीं करते हैं, इसलिए उनके खिलाफ सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकारों को सूचना और सर्वोत्तम तरीको को साझा करने के लिए साई के साथ मिलकर काम करना चाहिए, और साइबर खतरों का मुकाबला करने के प्रयासों का समन्वय करना चाहिए।

Excellencies,

17. मैं सुशासन को बढ़ावा देने, सामाजिक और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और आवश्यक निगरानी प्रदान करने और कुशल और प्रभावी ऑडिट के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों को लैस करने की आवश्यकता को बताने के लिए सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर बातचीत और उपयोगी चर्चा करने के लिए तत्पर हूं। मेरा दृढ़ मत है कि सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से साइबर सुरक्षा से संबंधित समस्याएं सामने आई हैं और इस प्रकार साइबर सुरक्षा मामलो

की लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त क्षमता विकसित करना साई के लिए अनिवार्य हो रहा है।

18. एक बार फिर, आप सब का हार्दिक अभिनंदन है । मैं कामना करता हूं कि आप सबका लखनऊ प्रवास अविस्मरणीय रहे। अब मैं उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोद्या श्रीमती आनंदीबेन पटेल से अनुरोध करता हूं कि आप बैठक का शुभारंभ करें ।

BSC/SS/TT/8-23